आगरा, प्रयागराज में नए औद्योगिक शहर

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, 9 अन्य राज्यों में भी बनेंगे 10 नए औद्योगिक शहर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज में नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब समेत 9 अन्य राज्यों में भी 10 नए औद्योगिक शहर बनेंगे।

28,602 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाले इन शहरों से करीब दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार व नियोजित औद्योगिकीकरण से 30 लाख परोक्ष नौकरियां पैदा होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मंत्रिमंडल की राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी के बाद देश में ऐसे शहरों की संख्या बीस हो जाएगी। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने व रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। इन शहरों की परिकल्पना छह प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है। ये परियोजनाएं देश की विनिर्माण क्षमताओं व आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण होंगी।

40
लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

28,602
करोड़ रुपये का निवेश होगा

उत्तराखंड समेत यहां बनेंगे नए औद्योगिक शहर

उत्तराखंड के खुरपिया, उत्तर प्रदेश के आगरा व प्रयागराज, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल एवं कोप्पर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली।

यूपी के 32 शहरों में शुरू होंगे निजी एफएम रेडियो

मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी है। 784.87 करोड़ रुपये की लागत से 730 चैनल शुरू होंगे। इस कदम से मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नए क्षेत्रों में कई आकांक्षी, नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

- उत्तर प्रदेश के अकबरपुर, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद/अयोध्या, फर्रुखाबाद कम फतेहगढ़, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, जौनपुर, लखीमपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मऊनाथ भंजन (मऊ), मिर्जापुर कम विंध्याचल, उरई, रायबरेली, शिकोहाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर में तीन-तीन जबकि मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर में चार-चार चैनल खोले जाएंगे।

औद्योगिक शहर बनाने का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार पैदा होंगे। कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार का फैसला किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

1.52 लाख करोड़ के निवेश की क्षमता

वैष्णव ने कहा, औद्योगिक गलियारों से रोजगार के अहम अवसर पैदा होने की उम्मीद है। न सिर्फ आजीविका के अवसर मिलेंगे, बल्कि उन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी योगदान मिलेगा, जहां ये परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता पैदा होगी।

एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष का दायरा बढ़ा

कृषि से जुड़ी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत करने के मकसद से केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने एआईएफ के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में एकीकृत प्राथमिक द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करने का फैसला किया है। >> पेज 10